West Bengal has been a pioneer in the field of manufacturing telecommunication cables for the last 30 years achieving higher production, profit and productivity and running with optimum efficiency;

(b) whether because of obsolescence of technology the production of paper insulated dry core cables at Rupnarayanpur, West Bengal, is likely to be stopped by 1988-89 and whether the proposal for expansion of 18 lakh CKM Jelly Filled cable as placed by HCL Rupnarayanpur unit in the year of 1981, which was duly recommended by pre-PIB and PIB, to replace the obsolescent technology has been approved by Government.

(c) if not, what are the reasons therefor;

(d) if expansion for replacement of paper insulated cable by Jelly Filled Cables is not agreed to by Govt. whether the unit is likely to become a sick industry within a few years time and if so, what is the alternative proposal of Government to make this industry viable; and

(e) whether the optical fibre project is proposed to be set up at Allahabad in the State of Uttar Pradesh despite the fact that infrastructural facilities and huge industrial experience are abundantly available at HCL Rupnarayanpur unit?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Rupnarainpur Unit of Hindustan Cables Limited (HCL) which was set-up in 1954 has, by and large, been achieving a significant growth in production, sales and profit.

(b) to (d) The Department of Telecommunications have indicated their intention to HCL to phase out the purchase of Dry Core Cables manufactured by HCL by the end of 1989-90. HCL have submitted schemes to Govt. for conversion of their existing capacity for Dry Core Cables to that for Jelly Filled Cables.

HCL's proposal for expansion of capacity by 18 lakh Conductor Kilometers (CKM) for manufacture of Jelly Filled Cables at Rupnarainpur Unit was earlier considered by Govt. but was deferred pending finalisation of targets of the Telecommunications sector for 7th Plan. However, owing to demand as also resource constraint, no further progress could be made so far. Meanwhile, the company has been advised to revise the cost estimates of the project. HCL have also proposed some diversification/modernisation schemes. With the implementation of the above schemes the company would continue to be viable.

(e) After taking into consideration all the relevant factors, it has been decided to locate the proposed Optical Fibre Project at Naini, Distt. Allahabad (UP).

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के एकक

2251. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**
श्री राम अवधेश सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर 1987 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "37 स्टेट यूनिट्स लूज रुपीज 130 करोड़" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) 1987-88 के प्रथम छः मास के दौरान और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सरकारी उद्यम विभाग के 37 उद्यमों के उत्पादन और लाभदेयता के अन्तिम और गैर-लेखा परीक्षित अनुमानों के रुख को नीचे तालिका 1 और 2 में दर्शाया गया है :-

तालिका-1

उत्पादन/कारोबार अनुमान

(करोड़ रु० में)

	अप्रैल-सितम्बर 1986-87	अप्रैल-सितम्बर 1987-88	प्रतिशत वृद्धि
इंजीनियरी एकक	1565	1857	(+) 19%
गैर-इंजीनियरी निर्माता एकक	186	249	(+) 34%
योग :	1751	2106	(+) 20%
परामर्शद यी/ठेका लेने वाले एकक	46	45	—

तालिका-2

लाभदेयता के अनुमान

(करोड़ रु० में)

	अप्रैल-सितम्बर 1986-87	अप्रैल-सितम्बर 1987-88
इंजीनियरी एकक . . .	(−) 20.4	(−) 56.5
गैर-इंजीनियरी एकक . . .	(−) 63.4	(−) 58.5
परामर्शदायी/ठेका लेने वाले एक	(−) 11.7	(−) 18.2
समग्र	(−) 95.5	(−) 133.2

मुख्यरूप से मजदूरी में संशोधन/अन्तरिम सहायता प्राकृतिक विपदायें जैसे बाढ़/अकाल, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई आदि के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ की वजह से हानि 95.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 133.2 करोड़ रुपए हो गई।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन कार्य को सुधारने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में उपयोक्ता विभागों/मंत्रालयों के मध्य अन्तः कार्यवाही, वित्तीय संसाधनों पर और अधिक नियंत्रण, अधिष्ठापित्र सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, लागत पर बेहतर नियंत्रण, बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबन्ध आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुझाव भी दिया गया है कि सम्मिलित उद्देश्यों के अनुरूप दीर्घकालिक और वार्षिक कार्य-चालन योजनाओं को प्रारम्भ करें। ऐसी योजनाओं को लागू करने और उपक्रमों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादकता को बढ़ाने और लागत में कमी करने के उद्देश्यों को देखते हुए इन समस्याओं को हल करने के संबंध में सुधारात्मक उपायों का समय पर पता लगाने के लिए उत्पादन की समय-समय पर व्यापक समीक्षा की जाती है।